भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

यूपीएससी प्रासंगिकता

GS Paper II : शासन और प्रशासनिक सुधार, लोक प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका, नैतिक शासन और सार्वजनिक विश्वास

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के भुवनेश्वर में "गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से 17-18 जुलाई, 2025 को आयोजित किया जा रहा है।
- सम्मेलन का विषय, "गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस" है, जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों से सम्मानित अनुकरणीय शासन पहलों को उजागर करना चाहता है।
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से आयोजित 41 सुशासन सम्मेलनों में से, 29 का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान प्रभावशाली ढंग से किया गया है।
- 1,600 से ज़्यादा अप्रचलित और पुराने क़ानून निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक बोझ काफ़ी कम हुआ है और शासन में बेहतर दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है।"

चार महत्वपूर्ण आयामों पर विस्तार से चर्चा:

1. पुरानी प्रथाओं से हटकर और लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को चुनौती दिया जाना।
2. दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर ज़ोर, खासकर जमीनी स्तर पर, जहां सेवा वितरण में सुधार हुआ है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
3. जिन सुधारों ने आम नागरिक की मानसिकता को मौलिक रूप से बदल दिया है, और व्यवस्था में आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास और विश्वास की एक नई भावना पैदा की है।
4. कई पहल—जैसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र—नवीन शासन के वैश्विक मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं।

CPGRAMS –

भारत सरकार द्वारा एक ई-गवर्नेंस पहल के रूप में शुरू की गई एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य नागरिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों को तेज़ी से और प्रभावी रूप से निपटाने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है। इसे लोक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।

निष्कर्ष:

इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लोक प्रशासन के प्रमुखों को एक एकीकृत मंच पर लाकर सहयोगात्मक शिक्षण और संस्थागत नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन लोक सेवा वितरण, डिजिटल शासन, नागरिक सहभागिता और समावेशी विकास में मापनीय और अनुकरणीय मॉडलों का प्रदर्शन करेगा।

Result Mitra

PYQ

1. प्रश्न: भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन सी पहलें शुरू की हैं? UPSC Prelims 2020

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
2. स्वच्छ भारत मिशन
3. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)
4. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)

सही उत्तर: 1 और 3

2. प्रश्न:'सुशासन' (Good Governance) की अवधारणा से निम्नलिखित में से कौन सी पहलें संबंधित हैं? UPSC Prelims 2019

1. केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)
2. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA)
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)
4. वस्तु एवं सेवा कर (GST)

सही उत्तर: 1 और 3

PYQ MAINS

प्रश्न:1. "'Good Governance' (सुशासन) की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें।(15 अंक)

UPSC Mains 2020

प्रश्न:2. "ई-गवर्नेंस की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? सार्वजनिक प्रशासन में इसके भूमिका पर चर्चा करें। (15 अंक)

UPSC Mains 2019

प्रश्न: 3. "भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रणाली की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख सुधार क्या हैं? (15 अंक)

UPSC Mains 2018

प्रश्न: 4. "जवाबदेही और पारदर्शिता सुशासन के दो प्रमुख घटक हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से इन घटकों को भारत में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?

UPSC Mains 2016